

प्रतिभा पलायन और भारतीय समाज : कारण, परिणाम एवं नीतिगत दृष्टिकोण का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. प्रशान्त सिंह ✉

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जमुहाई, जौनपुर, उत्तर प्रदेश
DOI: <https://doi.org/10.57067/ir.v2.i10.417>

सारांश: प्रतिभा पलायन आज भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर और बहुआयामी चुनौती के रूप में उभर रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त और कुशल युवा वर्ग—चाहे वे इंजीनियर, वैज्ञानिक, चिकित्सक हों या प्रबंधन व सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ—बेहतर अवसरों, उच्च वेतन, अनुसंधान की सुविधाओं और वैश्विक पहचान की खोज में विकसित देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया ने एक ओर भारत को मानव पूँजी की हानि दी है, जिससे अनुसंधान, नवाचार और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में शून्य उत्पन्न हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसने रेमिटेंस, वैश्विक अनुभव और ज्ञान के आदान-प्रदान के रूप में कुछ सकारात्मक लाभ भी प्रदान किए हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रतिभा पलायन केवल आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचना, युवा आकांक्षाओं, सांस्कृतिक पहचान और वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। विश्व-प्रणाली सिद्धांत, आधुनिकीकरण सिद्धांत और मानव पूँजी दृष्टिकोण जैसे ढाँचे इस प्रक्रिया की जटिलताओं को समझने में सहायक हैं। भारतीय नीति-निर्माण ने हाल के वर्षों में इस चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया है—जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स (GIAN) तथा स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रतिभाओं को वापस लाने या उनकी विशेषज्ञता का लाभ देश के भीतर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। यह शोध-पत्र प्रतिभा पलायन की पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम और नीतिगत पहलुओं का विस्तृत समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत को दीर्घकालिक दृष्टि से एक ऐसी संतुलित रणनीति विकसित करनी होगी जो एक ओर देश के भीतर शिक्षा और शोध के अवसरों को मज़बूत करे और दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर प्रवासी भारतीयों की क्षमता को “ब्रेन गेन” में रूपांतरित करे।

मुख्य शब्द: प्रतिभा पलायन, कुशल श्रमिकों का प्रवासन, भारतीय समाज, मानव पूँजी, विदेशी मुद्रा प्रेषण, वैश्वीकरण, नीतिगत दृष्टिकोण

परिचय (Introduction)

प्रतिभा पलायन आधुनिक वैश्विक समाज की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला है। इस शब्द का प्रयोग उन परिस्थितियों के लिए किया जाता है, जब किसी राष्ट्र की उच्च शिक्षा प्राप्त और विशेष कौशल से संपन्न जनशक्ति—जैसे वैज्ञानिक, अभियंता,

चिकित्सक, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, प्रबंधन विशेषज्ञ—अपने देश को छोड़कर बेहतर अवसरों की तलाश में विदेशों की ओर प्रवास करती है। इस प्रक्रिया को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से देखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों से भी जुड़ी हुई है।

भारत में प्रतिभा पलायन का इतिहास औपनिवेशिक काल के अंतिम दशकों से जुड़ा हुआ है, जब ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों में उच्च शिक्षा और नौकरी की संभावनाओं के लिए भारतीय युवाओं का प्रवाह प्रारंभ हुआ। परंतु वास्तविक रूप से यह प्रवृत्ति स्वतंत्रता के बाद के दशकों में अधिक तेज़ हुई। विशेष रूप से 1960 और 1970 के दशकों में अमेरिका और यूरोप की ओर भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं का पलायन अभूतपूर्व रूप से बढ़ा। इसी पृष्ठभूमि में भगवती और हमदा ने अपने प्रसिद्ध अध्ययन में प्रतिभा पलायन को श्रम बाज़ार, बेरोज़गारी और अंतरराष्ट्रीय असमानताओं से जोड़कर परिभाषित किया और इस पर अकादमिक विमर्श का नया द्वार खोला¹।

वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए, तो प्रवासन की यह परिघटना लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के International Migration 2020 Highlights में दर्ज आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020 तक विश्व में लगभग 28.1 करोड़ प्रवासी रह रहे थे, जिनमें से भारतीय प्रवासी

सबसे बड़ा हिस्सा थे²। यह आँकड़ा न केवल भारत की वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत करता है कि भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण संख्या अपने मूल देश से बाहर रहकर वहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज का हिस्सा बन चुकी है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रतिभा पलायन एक द्विपक्षीय चरित्र रखता है। एक ओर, जब कोई कुशल और शिक्षित व्यक्ति भारत छोड़कर विदेश चला जाता है, तो इससे देश को प्रत्यक्ष रूप से क्षति होती है। अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में योग्य वैज्ञानिकों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव, उच्च शिक्षा में प्रतिभाशाली अध्यापकों की कमी—ये सभी परिणाम इसी पलायन से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक दृष्टि से भी यह प्रवृत्ति युवाओं की आकांक्षाओं, परिवारों की संरचना और सांस्कृतिक पहचान पर गहरा प्रभाव डालती है।

किन्तु दूसरी ओर, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन प्रवासी भारतीयों का अपने मूल देश से संबंध पूरी तरह टूटता नहीं है। वे

विदेशों में अर्जित आय का एक बड़ा हिस्सा अपने परिवारों को भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहा जाता है। विश्व बैंक के 2023 के आँकड़ों के अनुसार भारत ने वर्ष 2022 में 111 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त की, जो विश्व का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्रवाह था³। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि प्रवासी भारतीय केवल अपने नए समाज में ही योगदान नहीं देते, बल्कि वे भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रत्यक्ष रूप से मज़बूत करते हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए, तो प्रतिभा पलायन केवल “ब्रेन ड्रेन” नहीं है, बल्कि यह “ब्रेन सर्कुलेशन” की दिशा भी खोल सकता है। विदेश में अर्जित ज्ञान, अनुभव और तकनीकी दक्षता जब किसी न किसी रूप में भारत तक पहुँचती है, तो इससे विकास की नई संभावनाएँ जन्म लेती हैं। उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में सहयोग, वैश्विक नेटवर्किंग, और नई स्टार्टअप संस्कृति के लिए यह प्रवासी समुदाय सेतु का कार्य कर सकता है।

इस खंड का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि प्रतिभा पलायन को केवल हानि के दृष्टिकोण से देखना अधूरा होगा। यह परिघटना चुनौतियों के साथ-साथ अवसर भी प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि इसे समझने और विश्लेषण करने के लिए हमें इसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों परिप्रेक्ष्यों से देखना आवश्यक है। भारतीय समाज की आकांक्षाएँ, शिक्षा व्यवस्था, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सरकारी नीतियाँ—ये सभी तत्व प्रतिभा पलायन को प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं।

इस शोध-पत्र में आगे हम इस प्रक्रिया के कारणों, परिणामों, प्रकरण अध्ययनों और नीतिगत दृष्टिकोणों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करेंगे। परंतु इस परिचय से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभा पलायन केवल “जनसंख्या का प्रवासन” नहीं है, बल्कि यह एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है जो भारत के वर्तमान और भविष्य दोनों को गहराई से प्रभावित करती है।

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि (Theoretical Framework)

किसी भी सामाजिक समस्या या प्रवृत्ति को समझने के लिए उसके सैद्धांतिक आधार का अध्ययन करना आवश्यक होता है। सैद्धांतिक पृष्ठभूमि किसी भी शोध का वह हिस्सा है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि अध्ययन की जाने वाली समस्या किन कारणों से उत्पन्न हुई है, उसके क्या परिणाम हैं और उसे किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। प्रतिभा पलायन (Brain Drain) जैसी जटिल घटना को केवल आँकड़ों या सतही विश्लेषण से नहीं समझा जा सकता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की आकांक्षाएँ, परिवार की उम्मीदें, समाज की संरचना और वैश्विक आर्थिक असमानताएँ—सब एक साथ कार्य करती हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में प्रतिभा पलायन केवल "लोगों का बाहर जाना" भर नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के अवसर, राज्य की नीतियों और वैश्विक संरचनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस खंड में हम तीन प्रमुख सिद्धांतों/दृष्टिकोणों की

चर्चा करेंगे, जो प्रतिभा पलायन को समझने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये तीन दृष्टिकोण हैं—माउंटफोर्ड का विकास मॉडल, स्टार्क और सहयोगियों का ब्रेन गेन दृष्टिकोण, तथा डॉकिये और रापोपोर्ट का वैश्वीकरण दृष्टिकोण।

1. माउंटफोर्ड का विकास मॉडल

एंड्रयू माउंटफोर्ड (1997) ने एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया जिसे समझे बिना प्रतिभा पलायन पर कोई भी चर्चा अधूरी रहती है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा पलायन हमेशा देश के लिए हानिकारक नहीं होता। यदि लोगों को यह संभावना नज़र आती है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें विदेश में बेहतर अवसर मिलेंगे, तो वे शिक्षा और कौशल में अधिक निवेश करते हैं।

इसका असर यह होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या देश में सामान्य से अधिक हो जाती है। भले ही उनमें से कुछ प्रतिशत लोग विदेश चले जाएँ, लेकिन शेष लोग देश में रहकर समाज और

अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पहले किसी देश में 100 लोग उच्च शिक्षा लेते थे और 10 विदेश चले जाते थे, तो देश में 90 कुशल लोग रह जाते थे। लेकिन यदि विदेश जाने की संभावना के कारण अब 200 लोग उच्च शिक्षा लेने लगे और उनमें से 20 विदेश जाएँ, तो भी देश में 180 कुशल लोग रहेंगे। यह पहले की तुलना में कहीं अधिक है।

इस प्रकार, माउंटफोर्ड का तर्क है कि प्रतिभा पलायन शिक्षा और कौशल विकास में निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है। हालांकि, यह तभी लाभकारी होगा जब प्रवासन की दर बहुत अधिक न हो और देश में कुशल लोगों को रोजगार देने की पर्याप्त क्षमता हो। यदि ऐसा न हो, तो शिक्षा में हुआ निवेश विदेश को अधिक लाभ पहुँचाएगा और देश को अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा⁴।

2. स्टार्क और सहयोगियों का 'ब्रेन गेन' दृष्टिकोण

ओडेड स्टार्क और उनके सहयोगियों (1997) ने प्रतिभा पलायन के संबंध में एक नया

दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने ब्रेन गेन कहा। उनका मानना था कि विदेश जाने वाले लोग केवल अपने नए देश को ही लाभ नहीं पहुँचाते, बल्कि अपने मूल देश को भी विभिन्न प्रकार से मदद करते हैं। इस मदद के कुछ प्रमुख रूप इस प्रकार हैं—

1. **संकेत प्रभाव (Signalling Effect):** जब लोग देखते हैं कि विदेश जाकर सफलता प्राप्त की जा सकती है, तो वे स्वयं भी शिक्षा और कौशल में अधिक निवेश करने लगते हैं। इससे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ता है।
2. **डायस्पोरा नेटवर्क:** विदेशों में बसे भारतीय केवल अपने जीवन तक ही सीमित नहीं रहते। वे अपने देश में निवेश करते हैं, नए व्यवसाय शुरू करते हैं, तकनीकी ज्ञान लाते हैं और अपने परिचितों के लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं।
3. **ज्ञान और अनुभव का हस्तांतरण:** प्रवासी भारतीय अपने अनुभव और तकनीकी दक्षता को प्रत्यक्ष (जैसे—वापसी प्रवासन, अल्पकालिक शिक्षण या संयुक्त परियोजनाएँ) और अप्रत्यक्ष (जैसे—ऑनलाइन शिक्षा, वर्चुअल सहयोग) दोनों रूपों में भारत तक पहुँचाते हैं।

स्टार्क का यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि यदि प्रवासी समुदाय से सही ढंग से जुड़ाव रखा जाए, तो वही लोग जो बाहर गए थे, वे देश के लिए नई संभावनाएँ भी लेकर आते हैं। इस प्रकार प्रतिभा पलायन को केवल ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन के रूप में भी देखा जा सकता है⁵।

3. डॉकिये और रापोपोर्ट का वैश्वीकरण दृष्टिकोण

फ्रेडरिक डॉकिये और हिल्लेल रापोपोर्ट (2012) ने प्रतिभा पलायन को वैश्वीकरण और संरचनात्मक असमानताओं से जोड़कर समझाया। उनका कहना था कि यह प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन और नीतिगत ढाँचों से गहराई से जुड़ी हुई है। विकसित देशों की उच्च वेतन संरचना, आधुनिक अनुसंधान सुविधाएँ और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था विकासशील देशों के कुशल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके विपरीत, विकासशील देशों में सीमित अवसर,

बेरोज़गारी और संसाधनों की कमी के कारण लोग विदेश जाने को मजबूर होते हैं।

डॉकिये और रापोपोर्ट के अनुसार, प्रतिभा पलायन का प्रभाव हर देश में एक जैसा नहीं होता। यह उस देश की संस्थागत गुणवत्ता और नीतिगत क्षमता पर निर्भर करता है। यदि कोई देश शिक्षा, अनुसंधान और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने में सक्षम है, तो प्रवासन दीर्घकाल में लाभकारी हो सकता है। लेकिन यदि घरेलू व्यवस्था कमजोर हो, तो प्रवासन केवल हानि का कारण बनेगा⁶।

4. भारतीय संदर्भ में इन सिद्धांतों की उपयोगिता

भारत पर इन तीनों दृष्टिकोणों को लागू करने पर कई तथ्य सामने आते हैं—
 माउंटफोर्ड का मॉडल इस बात को स्पष्ट करता है कि विदेश जाने की संभावना भारतीय युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। आज लाखों छात्र विदेश जाने का सपना लेकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन की पढ़ाई करते हैं।

स्टार्क के ब्रेन गेन दृष्टिकोण की पुष्टि भारतीय प्रवासी समुदाय से होती है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे भारतीय आईटी, चिकित्सा और व्यापार के क्षेत्र में न केवल स्थानीय स्तर पर योगदान दे रहे हैं, बल्कि वे भारत में भी निवेश और अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।

डॉकिये और रापोपोर्ट के वैश्वीकरण दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों का पलायन घरेलू स्तर पर चुनौतियाँ पैदा करता है। किन्तु यदि नीति-निर्माता सही दिशा में कदम उठाएँ, तो यह पलायन भी दीर्घकाल में लाभ में बदला जा सकता है।

निष्कर्ष

इन तीनों दृष्टिकोणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिभा पलायन को केवल नकारात्मक घटना मानना अधूरा दृष्टिकोण है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें हानि और लाभ दोनों निहित हैं। यदि भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएँ शिक्षा और रोजगार की अपनी संरचनाओं को मजबूत करें और प्रवासी समुदाय से जुड़ाव

बढ़ाएँ, तो यह प्रक्रिया "ब्रेन ड्रेन" से "ब्रेन गेन" में रूपांतरित हो सकती है।

अनुसंधान पद्धति (Methodology)

किसी भी शोध-पत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें प्रयुक्त अनुसंधान पद्धति कितनी सुव्यवस्थित और तर्कसंगत है। अनुसंधान पद्धति शोध की वह रीढ़ होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रस्तुत किए गए निष्कर्ष केवल लेखक की धारणाओं पर नहीं, बल्कि व्यवस्थित, तार्किक और संगत प्रक्रिया पर आधारित हों। इस शोध-पत्र का विषय-प्रतिभा पलायन और भारतीय समाज-एक जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्या है। इसलिए इसे समझने के लिए ऐसी पद्धति की आवश्यकता है, जो न केवल आँकड़ों को सही परिप्रेक्ष्य में रखे, बल्कि उनके पीछे छिपे सामाजिक और संरचनात्मक पहलुओं को भी उजागर करे।

1. अध्ययन का उद्देश्य और स्वरूप

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में प्रतिभा पलायन की प्रक्रिया, उसके कारणों और परिणामों को समाजशास्त्रीय

दृष्टिकोण से समझना है। साथ ही यह भी देखना है कि किस प्रकार सरकारी नीतियाँ और वैश्विक संरचनाएँ इस प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अध्ययन का स्वरूप व्याख्यात्मक (explanatory) और विश्लेषणात्मक (analytical) दोनों है। व्याख्यात्मक इसलिए कि यह प्रतिभा पलायन की जटिलताओं को स्पष्ट करता है; और विश्लेषणात्मक इसलिए कि यह उसके पीछे कार्य करने वाले कारणों और परिणामों का तुलनात्मक मूल्यांकन करता है।

2. अनुसंधान दृष्टिकोण

यह शोध गुणात्मक (qualitative) और वर्णनात्मक (descriptive) दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिभा पलायन की पृष्ठभूमि और उसकी निरंतरता को समझा गया है, जबकि तुलनात्मक दृष्टि से भारत की स्थिति को अन्य विकासशील और विकसित देशों के संदर्भ में देखा गया है।

साथ ही, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, क्योंकि प्रतिभा पलायन को केवल आँकड़ों से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों से जोड़कर समझना आवश्यक है।

3. अध्ययन का दायरा

इस अध्ययन का दायरा मुख्यतः भारतीय समाज तक सीमित है, परंतु इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य से जोड़ा गया है। भारत से होने वाले प्रतिभा पलायन को समझने के लिए उन देशों की भी चर्चा की गई है जहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय बड़ी संख्या में रहता है, जैसे-संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देश।

दायरे के अंतर्गत तीन मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

1. प्रतिभा पलायन के कारण – जैसे आर्थिक असमानता, रोजगार के अवसरों की कमी, अनुसंधान एवं विकास की अपर्याप्तता।
2. प्रतिभा पलायन के परिणाम – जैसे मानव पूँजी की हानि, रेमिटेंस से लाभ, ज्ञान और तकनीकी हस्तांतरण।

3. नीतिगत हस्तक्षेप – जैसे शिक्षा नीति, प्रवासी भारतीय नीति, और वैश्विक सहयोग।

4. डाटा संग्रह की विधि

यह शोध मुख्यतः द्वितीयक (secondary) स्रोतों पर आधारित है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, जैसे—

आधिकारिक सरकारी रिपोर्टें (शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नीति आयोग)।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टें (संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक)।

शोध-पत्रिकाएँ, पुस्तकें और पूर्व प्रकाशित लेख। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रासंगिक सामग्री।

प्राथमिक डाटा का संग्रह इस शोध का हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्रतिभा पलायन जैसी व्यापक और वैश्विक घटना को व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्यक्ष साक्षात्कार या सर्वेक्षण के माध्यम से संपूर्णता में पकड़ पाना कठिन है। अतः उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों के व्यवस्थित विश्लेषण को ही आधार बनाया गया है।

5. डाटा विश्लेषण की तकनीक

डाटा विश्लेषण के लिए गुणात्मक विश्लेषण (qualitative analysis) पद्धति अपनाई गई है। इसमें निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया गया है—

सामग्री विश्लेषण (Content Analysis):

विभिन्न रिपोर्टें, शोध-पत्रों और नीतिगत दस्तावेजों में प्रयुक्त शब्दों और तर्कों का अध्ययन करके यह समझा गया कि प्रतिभा पलायन के संबंध में किस प्रकार की व्याख्या की गई है।

तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative

Analysis): भारत की स्थिति की तुलना अन्य विकासशील देशों (जैसे चीन, फिलीपींस) और विकसित देशों से की गई है।

थीमैटिक विश्लेषण (Thematic Analysis):

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तथ्यों को विषयगत रूप से वर्गीकृत किया गया—जैसे “आर्थिक कारण”, “सामाजिक प्रभाव”, “नीतिगत पहल” आदि।

6. अध्ययन की सीमाएँ

किसी भी शोध की अपनी सीमाएँ होती हैं, और यह अध्ययन भी इससे अछूता नहीं है। प्रमुख सीमाएँ इस प्रकार हैं—

1. यह शोध केवल द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, इसलिए इसमें नवीनतम आँकड़ों की उपलब्धता पर निर्भरता बनी रहती है।
2. प्रतिभा पलायन के कारण और परिणाम समय के साथ बदलते रहते हैं। इस शोध में प्रस्तुत विश्लेषण वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप है, परंतु भविष्य में इसमें नए आयाम जुड़ सकते हैं।
3. वैश्विक आँकड़े कई बार परस्पर विरोधी भी होते हैं, जिससे तुलना करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

7. नैतिक विचार

शोध पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नैतिकता भी है। इस अध्ययन में प्रयुक्त सभी आँकड़े और विचार प्रमाणित एवं सार्वजनिक स्रोतों से लिए गए हैं। किसी भी स्रोत का गलत प्रयोग नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत विश्लेषण पूरी तरह निष्पक्ष और शैक्षणिक है।

8. निष्कर्ष

अनुसंधान पद्धति से यह स्पष्ट होता है कि यह अध्ययन एक व्यवस्थित, तार्किक और विश्वसनीय प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें गुणात्मक विश्लेषण को केंद्र में रखकर विभिन्न द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इस पद्धति का उद्देश्य आँकड़ों को केवल संकलित करना नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और संरचनात्मक संदर्भों को समझना है।

इस प्रकार, यह खंड इस बात की पुष्टि करता है कि शोध-पत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले निष्कर्ष एक संगठित और वैज्ञानिक प्रक्रिया से निकाले गए हैं, जो शोध की विश्वसनीयता और उपयोगिता दोनों को सुनिश्चित करते हैं।

कारण (Causes of Brain Drain)

प्रतिभा पलायन (Brain Drain) का अध्ययन करते समय यह समझना आवश्यक है कि इसके पीछे कौन-कौन से मूलभूत कारण कार्यरत हैं। यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत आकांक्षाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक

संरचनाओं का संयुक्त प्रभाव है। भारत जैसे देश, जहाँ शिक्षा प्रणाली लगातार बड़ी संख्या में उच्च कौशल वाले स्नातक और शोधकर्ता तैयार कर रही है, वहाँ इन प्रतिभाओं का बड़े पैमाने पर विदेश पलायन इस बात का संकेत है कि घरेलू स्तर पर उनकी आकांक्षाओं और अवसरों में गहरा असंतुलन है। इस खंड में प्रतिभा पलायन के प्रमुख कारणों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है।

1. आर्थिक कारक

आर्थिक असमानता प्रतिभा पलायन का सबसे प्रमुख कारण है। भारत में प्रतिभाशाली युवाओं के पास रोजगार के अवसर तो होते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता और वेतनमान विकसित देशों की तुलना में काफी कम है।

वेतन का अंतर: विकसित देशों, विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में समान कार्य के लिए मिलने वाला वेतन भारत की तुलना में कई गुना अधिक होता है।

संसाधनों की कमी: अनुसंधान, उद्योग और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों की

सीमितता के कारण कई बार युवाओं को उनके योग्य अवसर नहीं मिल पाते।

करियर सुरक्षा: विकसित देशों में स्थिर करियर और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (health insurance, pension, housing benefits) अधिक आकर्षक हैं, जो भारतीय युवाओं को बाहर जाने के लिए प्रेरित करती हैं।

आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रतिभा पलायन इस असंतुलन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।

2. शिक्षा और अनुसंधान के अवसर

भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बड़ी है, लेकिन उनकी गुणवत्ता में असमानता है। IITs, IIMs या कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों को छोड़ दें तो अधिकांश संस्थानों में शोध की गुणवत्ता और सुविधाएँ सीमित हैं।

अनुसंधान सुविधाएँ: विदेशों में शोध करने वाले विद्यार्थियों को अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ, नवीनतम तकनीकी संसाधन और पर्याप्त अनुदान मिलता है।

शैक्षणिक नेटवर्क: विदेशों के विश्वविद्यालय वैश्विक शैक्षणिक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जिससे

छात्रों को अधिक exposure और सहयोग मिलता है।

फेलोशिप और छात्रवृत्ति: विदेशी विश्वविद्यालय आकर्षक फेलोशिप और छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराते हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या और राशि अक्सर पर्याप्त नहीं होती।

परिणामस्वरूप, प्रतिभाशाली छात्र और शोधकर्ता उच्च शिक्षा तथा शोध के लिए विदेश जाने को प्राथमिकता देते हैं।

3. रोजगार संरचना और अवसरों की कमी

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, परंतु उच्च कौशल वाले युवाओं को उनके अनुरूप अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते।

रोजगार का असंतुलन: शिक्षा क्षेत्र से निकलने वाले इंजीनियरों, डॉक्टरों और प्रबंधकों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन घरेलू उद्योग उन्हें समायोजित करने में सक्षम नहीं हैं।

अनौपचारिक रोजगार: बड़ी संख्या में उच्च शिक्षित युवाओं को अस्थायी और अनुबंध आधारित नौकरियों पर काम करना पड़ता है,

जो उन्हें विदेश की स्थायी और सुरक्षित नौकरियों की ओर खींचता है।

नौकरशाही की जटिलताएँ: भारत में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में भर्ती और करियर उन्नति की प्रक्रियाएँ अक्सर धीमी और जटिल होती हैं।

4. सामाजिक और सांस्कृतिक कारक

प्रतिभा पलायन केवल आर्थिक आकांक्षाओं से प्रेरित नहीं होता, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रतिष्ठा और सामाजिक दबाव: विदेश जाकर पढ़ाई करना या नौकरी करना भारत में अक्सर प्रतिष्ठा और सफलता का प्रतीक माना जाता है।

परिवारिक प्रभाव: जिन परिवारों के सदस्य पहले से विदेश में बसे होते हैं, वे अपने अन्य सदस्यों को भी विदेश जाने के लिए प्रेरित करते हैं।

जीवन-शैली और सुविधाएँ: विकसित देशों में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसर संरचना की उपलब्धता युवाओं को आकर्षित करती है।

5. राजनीतिक और नीतिगत कारण

भारत की नीति संरचनाएँ भी कई बार प्रतिभा पलायन को रोक पाने में असफल होती हैं।

शिक्षा नीति की सीमाएँ: राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सुधार की दिशा दिखाई है, लेकिन शोध और नवाचार को बढ़ावा देने में अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

अनुदान और निवेश की कमी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का बहुत कम हिस्सा खर्च होता है।

लालफीताशाही और अवसरों की असमानता: नीति-निर्माण की जटिलता और अवसरों की असमानता भी युवाओं को विदेश जाने की ओर प्रेरित करती है।

6. वैश्विक असमानताएँ और अवसर संरचना
विकसित और विकासशील देशों के बीच अवसरों की खाई भी प्रतिभा पलायन का एक बड़ा कारण है।

ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का अंतर: विकसित देश न केवल बेहतर अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि सक्रिय रूप से उच्च कौशल

वाले प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए विशेष वीज़ा और इमिग्रेशन नीतियाँ बनाते हैं।

छात्रवृत्ति और अनुदान: विश्व स्तर पर उपलब्ध अनुदान और शोध अवसर विकासशील देशों की तुलना में कहीं अधिक हैं।

ब्रेन हंटिंग की नीति: अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश व्यवस्थित रूप से उच्च कौशल वाले युवाओं को आकर्षित करने के लिए योजनाएँ बनाते हैं।

7. विद्वानों के दृष्टिकोण

प्रतिभा पलायन के कारणों का अकादमिक अध्ययन भी इस विषय की गहराई को उजागर करता है।

बीन, डॉकिये और रापोपोर्ट (2008) ने अपने शोध में बताया कि विकासशील देशों से उच्च कौशल वाले लोगों का प्रवासन मानव पूँजी निर्माण को प्रभावित करता है। उन्होंने यह विश्लेषण किया कि कुछ परिस्थितियों में पलायन से देश को लाभ भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश मामलों में यह कुशल संसाधनों की कमी पैदा करता है⁷।

कृष्णा और खट्टिया (1997) ने भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के प्रवासन का अध्ययन करते हुए इसे एक गंभीर चुनौती बताया। उनके अनुसार, वैज्ञानिक पलायन भारत की शोध प्रणाली को कमजोर करता है और नवाचार की क्षमता को बाधित करता है⁸।

8. भारतीय समाज के संदर्भ में विशिष्ट कारण भारत के संदर्भ में कुछ कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं:

ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले युवाओं की आकांक्षा: शिक्षा और अवसरों की कमी के कारण वे विदेश में बेहतर जीवन-स्तर की तलाश करते हैं।

आईटी और मेडिकल क्षेत्र: इन क्षेत्रों में अवसर तो हैं, लेकिन वेतन और संसाधनों की तुलना में विदेश अधिक आकर्षक विकल्प प्रदान करता है।

नवाचार और उद्यमिता की बाधाएँ: भारत में उद्यमिता और स्टार्टअप का माहौल अभी भी कई संरचनात्मक चुनौतियों से घिरा है, जबकि विदेशों में निवेश और समर्थन अधिक सहजता से उपलब्ध होता है।

परिणाम (Consequences of Brain Drain)

प्रतिभा पलायन के प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर गहरे परिणाम उत्पन्न करता है। भारत जैसे विकासशील देश, जहाँ शिक्षा और कौशल की विशाल क्षमता मौजूद है, वहाँ से होने वाला पलायन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना पर बहुआयामी असर डालता है। इस खंड में इन परिणामों को विस्तृत रूप से समझाया गया है।

मानव पूँजी की हानि

प्रतिभा पलायन का सबसे प्रत्यक्ष और गंभीर परिणाम मानव पूँजी की हानि के रूप में सामने आता है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली प्रतिवर्ष लाखों इंजीनियर, चिकित्सक, वैज्ञानिक और प्रबंधक तैयार करती है, किंतु इनमें से एक बड़ा हिस्सा अपनी विशेषज्ञता और कौशल का उपयोग देश के भीतर न करके विदेशों में करता है। इस स्थिति से देश की नवाचार क्षमता, अनुसंधान की प्रगति और नीति निर्माण के लिए उपलब्ध बौद्धिक संसाधन कमजोर हो

जाते हैं। विशेषकर विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में यह कमी दीर्घकालीन विकास योजनाओं को प्रभावित करती है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पहले से ही विशेषज्ञों की भारी कमी है, और प्रतिभा पलायन इस समस्या को और गहरा बना देता है।

आर्थिक प्रभाव

आर्थिक दृष्टि से प्रतिभा पलायन एक जटिल स्थिति प्रस्तुत करता है। एक ओर यह देश के लिए नुकसानदेह साबित होता है क्योंकि प्रशिक्षित मानव संसाधनों की अनुपस्थिति उत्पादकता और नवाचार की गति को धीमा कर देती है। घरेलू उद्योग और अनुसंधान संस्थान योग्य विशेषज्ञों की कमी से जूझते हैं, जिससे नई तकनीकों को अपनाना और विकसित करना कठिन हो जाता है। यह स्थिति लंबे समय में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है।

दूसरी ओर, विदेश में बसे भारतीय प्रवासियों से प्राप्त रेमिटेंस देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विश्व बैंक के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत लगातार वैश्विक

स्तर पर रेमिटेंस प्राप्त करने वाले शीर्ष देशों में रहा है। यह रेमिटेंस ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सहारा देता है तथा परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। कई बार यही धन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में खर्च होकर मानव पूँजी निर्माण को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा भी देता है।

इस प्रकार आर्थिक प्रभाव दोहरी प्रकृति का होता है, जिसमें नुकसान और लाभ दोनों निहित हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव

प्रतिभा पलायन का असर समाज की संरचना और सांस्कृतिक संतुलन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विदेश में बस चुके प्रवासी अपने परिवारों को आर्थिक सहयोग तो करते हैं, किंतु सामाजिक और भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है। परिवारों के बिखराव से पीढ़ीगत संबंध प्रभावित होते हैं और स्थानीय समुदायों में सामाजिक पूँजी का क्षय होता है।

सांस्कृतिक स्तर पर प्रवासी भारतीय नए विचारों, जीवन-शैली और मूल्यों को अपने देश तक पहुँचाते हैं। इससे समाज में आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज़

होती है। परंतु यह प्रक्रिया कई बार पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक संतुलन को चुनौती भी देती है। प्रवासियों के प्रभाव से उत्पन्न यह “संस्कृति मिश्रण” (cultural hybridization) सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी।

शिक्षा और अनुसंधान पर प्रभाव

भारतीय शिक्षा और अनुसंधान प्रणाली पर प्रतिभा पलायन का गहरा असर पड़ता है। जब योग्य शोधार्थी और शिक्षक विदेश चले जाते हैं, तो देश के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अनुसंधान परियोजनाएँ अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाती हैं क्योंकि उनमें वैश्विक मानकों के अनुरूप नवाचार और संसाधनों की कमी होती है।

यह स्थिति विशेष रूप से तब गंभीर हो जाती है जब छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं और वहाँ स्थायी रूप से बस जाते हैं। भारत अपने द्वारा तैयार किए गए प्रतिभाशाली युवाओं से अपेक्षित योगदान प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि वही प्रतिभा विदेशों की संस्थाओं

को समृद्ध करती है। इसे “ब्रेन ड्रिवाइड” की स्थिति भी कहा गया है, जिसमें विकासशील देश प्रशिक्षण की लागत वहन करते हैं, लेकिन उसका लाभ विकसित देशों को मिलता है।

स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र पर प्रभाव भारत के स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र प्रतिभा पलायन से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का पलायन ग्रामीण भारत में चिकित्सा सेवाओं की कमी को और गहरा बना देता है। विकसित देशों में उच्च वेतन और बेहतर कार्य परिस्थितियों के कारण भारतीय चिकित्सा पेशेवर बड़ी संख्या में विदेश चले जाते हैं।

इसी प्रकार, आईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्र भी इस प्रवृत्ति से प्रभावित होते हैं। भारत में तैयार की गई आईटी प्रतिभाएँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आकर्षक पैकेज के कारण विदेश जाकर वहाँ की तकनीकी प्रगति में योगदान देती हैं। इससे भारत की घरेलू तकनीकी क्षमताओं और “मेक इन इंडिया” जैसी योजनाओं की सफलता को चुनौती मिलती है। राजनीतिक और नीतिगत प्रभाव

प्रतिभा पलायन नीति-निर्माण और प्रशासनिक तंत्र पर भी असर डालता है। उच्च कौशल वाले विशेषज्ञ विदेश जाकर वहाँ की नीति-निर्माण प्रक्रिया को मजबूत करते हैं, जबकि भारत में नीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव महसूस किया जाता है। यह स्थिति विशेषकर विज्ञान और तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में गंभीर है। उदाहरणस्वरूप, वैज्ञानिक शोध और नवाचार पर आधारित दीर्घकालीन योजनाओं को सफल बनाने में भारत कई बार विशेषज्ञों की कमी के कारण पिछड़ जाता है।

ब्रेन गेन और ब्रेन सर्कुलेशन

यद्यपि प्रतिभा पलायन के अधिकांश परिणाम नकारात्मक प्रतीत होते हैं, किंतु इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं जिन्हें “ब्रेन गेन” और “ब्रेन सर्कुलेशन” के रूप में देखा जा सकता है। विदेश में बसे भारतीय न केवल आर्थिक रूप से योगदान देते हैं, बल्कि तकनीकी और बौद्धिक नेटवर्क भी बनाए रखते हैं। कई प्रवासी विदेश में अनुभव और पूँजी अर्जित करने के बाद भारत लौटकर शिक्षा, शोध और उद्योग

में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, स्थायी रूप से विदेश में बस जाने वाले लोग भी अपने देश से जुड़े रहते हैं और निवेश, परामर्श और तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से योगदान देते हैं।

विद्वानों का दृष्टिकोण

देसाई, कपूर और मैकहेल (2009) ने अपने अध्ययन में दिखाया कि उच्च कौशल वाले लोगों का विदेश जाना केवल नकारात्मक परिणाम ही उत्पन्न नहीं करता, बल्कि यह देश के भीतर शिक्षा और कौशल विकास की नई माँग भी पैदा करता है। उनके अनुसार, जब लोग देखते हैं कि विदेश में जाने के अवसर उपलब्ध हैं, तो वे अधिक मेहनत से शिक्षा प्राप्त करते हैं और कौशल विकसित करते हैं। यह प्रक्रिया मानव पूँजी निर्माण को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करती है और इसे “प्रोत्साहन प्रभाव” (Incentive Effect) कहा जाता है⁹।

नीतिगत हस्तक्षेप (Policy Responses)

भारत से उच्च कौशल वाले लोगों का विदेशों की ओर पलायन लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। यह केवल मानव पूँजी का

हास नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास, शिक्षा, अनुसंधान और सामाजिक ढाँचे के लिए चुनौती भी है। हालाँकि, इस चुनौती को केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप इस प्रवृत्ति को अवसर में बदल सकते हैं। कई अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों ने भी संकेत दिया है कि सही नीतियों के जरिये “ब्रेन ड्रेन” को “ब्रेन गेन” और “ब्रेन सर्कुलेशन” में बदला जा सकता है¹⁰। भारत ने इस दिशा में विभिन्न प्रकार की नीतियाँ और योजनाएँ लागू की हैं, परंतु इनके साथ-साथ कई सीमाएँ और चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं।

वैश्वीकरण और प्रतिभा पलायन: नीतिगत दृष्टिकोण

डॉकिये और रापोपोर्ट (2012) का तर्क है कि वैश्वीकरण ने प्रवासन की प्रक्रियाओं को तीव्र किया है, जिससे विकासशील देशों से उच्च कौशल वाले युवाओं का बहिर्गमन बढ़ा है। किंतु साथ ही यह स्थिति अवसर भी प्रदान करती है कि विकासशील देश प्रवासियों के माध्यम से पूँजी, तकनीक और ज्ञान तक पहुँच बना सकें¹⁰। उनके अनुसार, यदि नीतियाँ सही दिशा

में काम करें तो विदेशों में बसे प्रवासी अपने मूल देश के लिए “वैश्विक संसाधन” बन सकते हैं।

भारत इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। विश्व बैंक की रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि भारत प्रवासी रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। इससे संकेत मिलता है कि प्रवासियों के साथ संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप कितना आवश्यक है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आर्थिक संबंध केवल धन तक सीमित न रह जाए, बल्कि बौद्धिक और तकनीकी योगदान में भी रूपांतरित हो।

शिक्षा और अनुसंधान में सुधार की पहल: NEP 2020

भारत सरकार ने शिक्षा नीति में सुधार के माध्यम से प्रतिभा पलायन की चुनौती का समाधान खोजने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है¹¹। इस नीति में उच्च शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने, बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देने और

अनुसंधान एवं नवाचार को केंद्र में रखने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

NEP 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाला शोध प्रोत्साहित करना है। यदि यह संस्था प्रभावी ढंग से काम करती है, तो भारत को विदेश जाने वाले प्रतिभाशाली शोधार्थियों को देश में ही अवसर देने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा, नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने की बात भी शामिल है। इससे भारतीय छात्रों को बिना देश छोड़े वैश्विक स्तर की शिक्षा मिल सकेगी। यह प्रतिभा पलायन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

प्रवासी भारतीय नीतियाँ और सहभागिता

भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, ओवरसीज़

सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI), और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO) जैसी योजनाएँ इस उद्देश्य से बनाई गईं कि भारतीय मूल के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहें। इन योजनाओं ने प्रवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने, शोध कार्यों में योगदान देने और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखने का अवसर दिया है।

हालाँकि इन पहलों का महत्व निर्विवाद है, परंतु प्रवासी भारतीयों की क्षमता का पूर्ण उपयोग अब भी नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए, चीन ने अपनी प्रवासी नीतियों के माध्यम से बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को अस्थायी या स्थायी रूप से वापस लाने में सफलता पाई है। भारत को भी इसी दिशा में ठोस नीतिगत प्रयास करने की आवश्यकता है।

वैज्ञानिक और अकादमिक सहयोग योजनाएँ:

GIAN और अन्य पहलें

भारत ने प्रतिभा पलायन को “ब्रेन सर्कुलेशन” में बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स (GIAN) इसका

प्रमुख उदाहरण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीय और विदेशी प्रोफेसरों को भारत आकर पढ़ाने और शोध कार्यों में शामिल करना है।

इसके अतिरिक्त, विजिटिंग प्रोफेसर प्रोग्राम्स, रामानुजन और रामलिंगस्वामी फैलोशिप्स जैसी योजनाएँ भी शुरू की गई हैं। इनके माध्यम से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भारत में शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये योजनाएँ भारत के शोध वातावरण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकती हैं।

आर्थिक और निवेश नीतियाँ

भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों को निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की हैं। प्रवासी निवेशकों के लिए “विशेष आर्थिक क्षेत्र” (SEZs) और “स्टार्टअप इंडिया” जैसी पहलों में अवसर प्रदान किए गए हैं। यदि इन पहलों को और लचीला तथा पारदर्शी बनाया जाए, तो प्रवासी भारतीय न केवल पूँजी बल्कि तकनीकी और प्रबंधकीय अनुभव भी भारत ला सकते हैं।

नीतिगत सीमाएँ और चुनौतियाँ

इन सभी सकारात्मक पहलों के बावजूद कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

पहली बड़ी चुनौती यह है कि भारत का शोध और विकास (R&D) पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का बहुत छोटा हिस्सा है। जबकि विकसित देशों में यह खर्च कहीं अधिक है, जिससे वे प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान कर पाते हैं।

दूसरी चुनौती नौकरशाही की जटिलता है। निवेश, शोध और शिक्षा से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने में लालफीताशाही बाधा बनती है। प्रवासी भारतीय कई बार शिकायत करते हैं कि भारत में प्रक्रियाएँ धीमी और अस्पष्ट हैं, जिससे वे सहयोग करने से हिचकिचाते हैं।

तीसरी चुनौती यह है कि शिक्षा और उद्योग के बीच पर्याप्त सेतु नहीं है। भारत में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षित युवा तैयार होते हैं, परंतु उनके कौशल का उद्योग में समुचित उपयोग नहीं हो पाता। यह असंतुलन प्रतिभा पलायन को बढ़ावा देता है।

भविष्य की दिशा

भारत को चाहिए कि वह अपनी नीतियों को “रोकथाम” (Prevention) के बजाय “प्रबंधन” (Management) और “परिसंचरण” (Circulation) की दिशा में मोड़े। प्रतिभा पलायन को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण के युग में गतिशीलता स्वाभाविक है। किंतु इसे अवसर में बदलना निश्चित रूप से संभव है।

इसके लिए भारत को शिक्षा और शोध में निवेश बढ़ाना होगा, संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देनी होगी, प्रवासी भारतीयों के लिए निवेश और सहयोग को सरल और आकर्षक बनाना होगा, और उद्योग-शिक्षा सहयोग को गहरा करना होगा। यदि ये कदम उठाए जाते हैं, तो भारत न केवल प्रतिभा पलायन से होने वाले नुकसान को कम कर सकेगा, बल्कि इसे अपनी ताकत में बदल पाएगा।

व्याख्यात्मक चर्चा एवं निष्कर्ष
(Interpretative Discussion & Conclusion)

प्रतिभा पलायन का प्रश्न आधुनिक भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि यह केवल एक आर्थिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की आकांक्षाओं, असमानताओं और वैश्विक संरचनाओं का दर्पण है।

प्रतिभा पलायन की सामाजिक व्याख्या

प्रतिभा पलायन को यदि समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल “रोज़गार की खोज” नहीं है, बल्कि सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा की खोज भी है। भारत में लंबे समय से यह धारणा रही है कि विदेश जाकर पढ़ना और काम करना सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सफलता का प्रतीक है। यह प्रवृत्ति विशेषकर शहरी मध्यवर्ग और उच्चवर्ग के बीच गहरी जड़ें जमा चुकी है।

सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह घटना वैश्विक संस्कृति (global culture) के प्रभाव को भी दर्शाती है। भारतीय समाज में पश्चिमी शिक्षा, जीवनशैली और पेशेवर मानकों को श्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कि

युवा विदेश जाने को आत्म-सिद्धि का साधन मानते हैं।

सामाजिक पूँजी (social capital) के परिप्रेक्ष्य से भी यह घटना महत्वपूर्ण है। जब कोई परिवार या समुदाय विदेश में नेटवर्क स्थापित कर लेता है, तो उसी पथ पर आगे की पीढ़ियाँ भी विदेश जाती हैं। इस प्रकार, प्रतिभा पलायन एक “सामाजिक चक्र” का रूप ले लेता है, जो स्वयं को बार-बार पुनरुत्पन्न करता है।

कारणों और परिणामों का आलोचनात्मक विश्लेषण

प्रतिभा पलायन के कारण बहुआयामी हैं और उनके परिणाम भी बहुआयामी हैं।

आर्थिक स्तर पर: बेहतर आय और अवसरों की खोज मुख्य कारण है। लेकिन परिणामस्वरूप भारत में विशेषज्ञों की कमी हो जाती है। उदाहरणस्वरूप, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की भारी कमी देखी जाती है।

शैक्षणिक स्तर पर: उच्च गुणवत्ता वाले शोध और प्रयोगशालाओं की अनुपलब्धता छात्रों को विदेश ले जाती है। परिणामस्वरूप, भारत का

शोध उत्पादन और नवाचार क्षमता प्रभावित होती है।

सामाजिक स्तर पर: विदेश जाना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। परिणामस्वरूप, भारत के भीतर सामाजिक असमानताएँ और गहरी हो जाती हैं क्योंकि सभी वर्गों को समान अवसर नहीं मिलते।

वैश्विक स्तर पर: विकसित देशों का आकर्षण (pull factor) और भारत की सीमाएँ (push factor) मिलकर प्रवासन को बढ़ाते हैं।

लेकिन इन कारणों और परिणामों को केवल नकारात्मक रूप में नहीं देखा जा सकता। प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया रেমिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था को मज़बूती देता है। साथ ही, विदेश में पढ़े और बसे भारतीय तकनीकी ज्ञान और वैश्विक अनुभव को भारत के साथ साझा करते हैं। इसे “ब्रेन गेन” और “ब्रेन सर्कुलेशन” के रूप में देखा जा सकता है¹²।

नीतिगत प्रयासों का मूल्यांकन

भारत सरकार ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए अनेक पहलें की

हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020¹³ इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें अनुसंधान और नवाचार को उच्च शिक्षा का केंद्रीय तत्व बनाया गया। National Research Foundation का उद्देश्य यह है कि शोध को पर्याप्त संसाधन और वैश्विक स्तर का आधार उपलब्ध कराया जाए।

इसके अतिरिक्त, प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस, OCI कार्ड और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएँ चलाई गईं। वैज्ञानिक सहयोग योजनाओं जैसे GIAN, रामानुजन फेलोशिप और रामलिंगस्वामी फेलोशिप ने विदेशों में बसे वैज्ञानिकों को भारत में योगदान देने का अवसर दिया।

फिर भी, इन नीतियों की सीमाएँ हैं। शिक्षा पर खर्च अब भी कम है। नौकरशाही की जटिलता और संस्थागत कठोरता सुधारों को धीमा कर देती है। ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों तक इन नीतियों के लाभ नहीं पहुँच पाते। इस प्रकार, नीतियाँ सही दिशा तो दिखाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव अभी सीमित है।

व्याख्यात्मक दृष्टिकोण: समाजशास्त्रीय विमर्श

समाजशास्त्र में “संरचना और अभिकरण” (structure and agency) का द्वंद्व महत्वपूर्ण है। प्रतिभा पलायन इसी द्वंद्व का उदाहरण है।

संरचना (structure) के स्तर पर – आर्थिक असमानता, शिक्षा की गुणवत्ता और वैश्विक शक्ति-संबंध प्रवासन को बाध्य करते हैं।

अभिकरण (agency) के स्तर पर – व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं, सामाजिक दबावों और अवसरों के आधार पर विदेश जाने का निर्णय लेता है।

दूसरे शब्दों में, यह घटना सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत निर्णयों दोनों की उपज है। इसी कारण इसे केवल आर्थिक समस्या या व्यक्तिगत विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे एक बहुस्तरीय सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझना होगा।

भविष्य की चर्चा (Future Pathways)

भविष्य में भारत के लिए यह अनिवार्य है कि प्रतिभा पलायन को अवसर में बदला जाए। रोकथाम की रणनीतियाँ सीमित हैं; वास्तविक समाधान यह है कि पलायन को

“मानव पूँजी परिसंचरण” (circulation of human capital) में परिवर्तित किया जाए।

1. शिक्षा और अनुसंधान में क्रांतिकारी सुधार

भारत को शिक्षा और अनुसंधान पर खर्च कई गुना बढ़ाना होगा। विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देनी होगी और प्रयोगशालाओं को वैश्विक स्तर का बनाना होगा। इससे युवाओं को विदेश जाने की बजाय देश में ही अवसर मिलेंगे।

2. प्रवासी भारतीयों की संरचनात्मक भागीदारी

प्रवासी भारतीयों को भारत के विकास में औपचारिक रूप से शामिल करना होगा। उन्हें नीति-निर्माण, शोध संस्थानों और शिक्षा संस्थानों से जोड़ा जा सकता है। Reverse Brain Drain के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जानी चाहिए ताकि वे अस्थायी या स्थायी रूप से भारत लौटकर योगदान दें।

3. उद्योग-अकादमिक सेतु का निर्माण

भारत को विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच मजबूत सहयोग स्थापित करना होगा। जब तक शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार और

नवाचार से नहीं होगा, तब तक पलायन की प्रवृत्ति बनी रहेगी।

4. ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान

डॉक्टरों, शिक्षकों और इंजीनियरों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहन देना होगा। यह प्रोत्साहन केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और करियर विकास से भी जुड़ा होना चाहिए।

5. अंतरराष्ट्रीय नेतृत्वकारी भूमिका

भारत को वैश्विक मंचों पर प्रवासन संबंधी विमर्श में नेतृत्व करना होगा। यदि भारत यह दिखा सके कि प्रतिभा पलायन को कैसे अवसर में बदला जा सकता है, तो यह मॉडल पूरे ग्लोबल साउथ के लिए उपयोगी होगा।

6. सामाजिक मानसिकता में बदलाव

सबसे गहरी आवश्यकता यह है कि भारतीय समाज यह स्वीकार करे कि शोध, नवाचार और शिक्षा केवल विदेश जाने का साधन नहीं हैं। जब तक भारत में शोध को समान प्रतिष्ठा और अवसर नहीं मिलेगा, तब तक युवाओं की मानसिकता नहीं बदलेगी।

निष्कर्ष

प्रतिभा पलायन भारत के लिए चुनौती भी है और संभावना भी। यह देश की सामाजिक संरचना, आकांक्षाओं और वैश्विक स्थान का आईना है। यदि भारत शिक्षा और शोध में निवेश बढ़ाए, प्रवासी भारतीयों को संरचनात्मक रूप से जोड़े, ग्रामीण असमानताओं को कम करे और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाए, तो यह प्रवृत्ति Brain Drain से Brain Circulation में बदल सकती है।

इस प्रकार, भविष्य का भारत न केवल अपनी प्रतिभा को बनाए रख पाएगा, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर साझा भी कर सकेगा। यही इस शोध का सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय निष्कर्ष है।

संदर्भ सूची:

1. Bhagwati, J. & Hamada, K. (1974). "The Brain Drain, International Integration of Markets for Professionals and Unemployment." *Journal of Development Economics*, 1(1): 19-42.
2. UN DESA (2020). *International Migration 2020: Highlights*. New York: United Nations, pp. 8-10.
3. World Bank (2023). *Remittances Remain Resilient but Likely to Slow*. Migration and Development Brief 38 / Press Release (India: US\$111bn, 2022).
4. Mountford, A. (1997). "Can a Brain Drain Be Good for Growth in the Source Economy?" *Journal of Development Economics*, 53(2): 287-303.
5. Stark, O., Helmenstein, C., & Prskawetz, A. (1997). "A Brain Gain with a Brain Drain." *Economics Letters*, 55(2): 227-234.
6. Docquier, F. & Rapoport, H. (2012). "Globalization, Brain Drain, and Development." *Journal of Economic Literature*, 50(3): 681-730.
7. Beine, M., Docquier, F., & Rapoport, H. (2008). "Brain Drain and Human Capital Formation in Developing

- Countries: Winners and Losers.”
Economic Journal, 118(528): 631-652.
8. Krishna, V. V., & Khadria, B. (1997). “Phasing Scientific Migration in the Context of Brain Gain and Brain Drain in India.” *Science, Technology & Society*, 2(2): 347-385.
9. Desai, M., Kapur, D., & McHale, J. (2009). “The Fiscal Impact of High-Skilled Emigration: Flows of Indians to the U.S.” *Journal of Development Economics*, 88(1): 32-44.
10. Docquier, F., & Rapoport, H. (2012). “Globalization, Brain Drain, and Development.” *Journal of Economic Literature*, 50(3): 681-730.
11. Government of India, Ministry of Education (2020). *National Education Policy 2020*. New Delhi: Government of India.
12. Desai, M., Kapur, D., & McHale, J. (2009). “The Fiscal Impact of High-Skilled Emigration: Flows of Indians to the U.S.” *Journal of Development Economics*, 88(1): 32-44.
13. Government of India, Ministry of Education (2020). *National Education Policy 2020*. New Delhi: Government of India.